

झारखण्ड स्वशासी परिषद : कुर्सी बन्दरबाटकी सरगर्मी तेज

आ

जादीके समयसे अलग झारखण्ड राज्यकी मांगको लेकर चला आ रहा आन्दोलन आखिरकार कुछ तो कारगर साबित हुआ, चलिये फिलहाल झारखण्ड स्वशासी परिषद ही सही। ये मिल जाय तो फिर अलग राज्यकी मांग तेज करेंगे। लगता है इस आन्दोलनसे जुड़ी झारखण्ड और अन्य पार्टियोंने यही सोचकर सन्तोष कर लिया है। इसलिए अब सबके सब जितना मिल रहा है उसीमें अपनी-अपनी कुर्सी सुरक्षित करनेकी जुगाड़में लग गये हैं। ११ जुलाईको बिहारके मुख्य मन्त्री लालूप्रसादने मन्त्रिमण्डलकी बैठक बुलायी और झारखण्ड स्वशासी परिषदका विधिवत गठन कर दिया।

परिषदका प्रशासनिक कामकाज चलानेके लिए अपर मुख्य सचिवके स्तरके आई. ए. एस. अधिकारीको मुख्य कार्यपालक पदाधिकारीके रूपमें नियुक्त किया जायगा। इस परिषदका अपना स्वतन्त्र कोष होगा और इस परिषदके अधीनस्थ १८ जिलोंकी योजनाके लिए बिहारकी वार्षिक योजनाकी कमसे कम २५ प्रतिशत राशिकी व्यवस्था की जायगी।

घोषणा हुई नहीं कि बिहारकी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी। सबसे पहले झारखण्ड मुक्ति मोर्चाके अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मण्डलने मौकापरस्तीका बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना राजनीतिक पैतरा बदला। अलग झारखण्ड राज्यके लिए लड़ रही ये वो सबसे बड़ी पार्टी है जिसके नेताओंका कहना था कि 'अलग राज्य' से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा और आदिवासियोंकी यह आकांक्षा पूरी हो नैतक आन्दोलन जारी रहेगा। लेकिन जिस स्वार्थपरताके चलते ५० वर्षोंमें यह आन्दोलन जोर नहीं पकड़ पाया, उसीका परिचय दिया शिबू सोरेनने। शिबू सोरेन और सूरज मण्डल दोनों ही श्री लालूप्रसादकी खुशामदमें लग गये ताकि अन्तरिम परिषदके अध्यक्षका पद कहीं उनके हाथसे निकल न जाय क्योंकि मनोनयनका अधिकार मुख्य मन्त्रीके हाथमें है। इसके लिए दोनोंने राष्ट्रीय मोर्चामें शामिल होनेका प्रस्ताव रखा जिसे मुख्य मन्त्री लालूप्रसादने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

दोनोंको लाभ मिला। शिबू सोरेनने दिल्लीमें पहलेसे ही गोटी सेट कर रखी है क्योंकि स्वशासी परिषदको सीधे केन्द्रसे पैसा मिलेगा

और परिषदका अध्यक्ष होनेके नाते सारे कोषोंका वारान्यारा वे अपनी मर्जीसे कर सकेंगे, साथ-साथ राज्य सरकारकी वार्षिक योजनाका लाभ भी उन्हें ही मिलेगा। श्री शिबू सोरेन झारखण्ड इलाकेमें किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी नेतासे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। इसलिए इसमें दो राय नहीं कि छः महीनेमें चुनाव होनेकी स्थितिमें झारखण्ड मुक्ति मोर्चाके सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी।

आदिवासी कल्याणके नामपर क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थके लिए चल रही इस जोड़तोड़में यह तय करना मुश्किल है कि वास्तवमें झारखण्ड स्वशासी परिषदके गठनका मार्ग प्रशस्त करनेका श्रेय किसे है। लालूप्रसाद यह कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि अलग राज्यका गठन तो केन्द्र सरकारके हाथमें है। राज्य सरकार इस मामलेमें कुछ नहीं कर सकती। केन्द्र सरकारके लिए इतना काफी था कि बिहार सरकारके अड़ंगेके कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस (इ) सरकारका दावा है कि स्वशासी परिषदका सारा इन्तजाम काफी पहले हो गया था, जनता दल सरकार उसे कार्यान्वित नहीं होने दे रही थी। 17.8.1995

आदिवासियोंकी दशामें कोई सुधार हो या न हो अपना घर भरनेका उन्हें पूरा अवसर मिलेगा। जैसा कि अबतक आदिवासी हितांके नामपर सारे झारखण्ड नेता करते रहे हैं।

सत्तारूढ़ जनता दल आदिवासी इलाकेमें आजतक अपना वोट बैंक नहीं बना पाया। खासकर इस वर्षके विधानसभा चुनावमें इस पार्टीके सर्वसर्वा लालू प्रसादजीको पहलेसे ज्यादा निराशाजनक स्थितिका सामना करना पड़ा है। इस चुनावमें जीत या तो झारखण्ड पार्टियोंको मिली अथवा भारतीय जनता पार्टीको। भारतीय जनता पार्टीको झारखण्ड जिलोंको मिलाकर अलग 'वर्नाचल' राज्यकी मांग बुलन्द करनेका लाभ मिला और उस मांगपर आज भी यह पार्टी अड़ी है। भाजपाकी प्रदेश शाखाके अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र बताते हैं कि स्वशासी परिषदका गठन आदिवासियोंको अपनी मूल मांगसे विमुख करनेका एक बहाना है, इसलिए उनकी पार्टी अलग वर्नाचल राज्यसे कम किसी भी बिन्दुपर समझौता नहीं करेगी।

लालूप्रसादजीने देखा कि झारखण्ड इलाकोंमें अपना प्रभाव जमानेका अब एक ही उपाय बच रहा है कि सबसे प्रभावशाली पार्टी झारखण्ड मुक्ति मोर्चाके साथ गठजोड़ किया जाय ताकि अगले वर्ष होनेवाले लोकसभा चुनावमें कमसे कम भाजपाको ज्यादा सीटें हासिल न होने पायें। यह जनता दल सरकारके हकमें अच्छा ही हुआ कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चाके नेता स्वयं उनसे सटने आये। मुख्य

बिहार सरकारके अड़ंगेके कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस (इ) सरकारका दावा है कि स्वशासी परिषदका सारा इन्तजाम काफी पहले हो गया था, जनता दल सरकार उसे कार्यान्वित नहीं होने दे रही थी। श्री लालूप्रसाद जोर देकर इस बातको कहते हैं कि जो काम अपने चालीस वर्षोंके शासनकी अवधिमें जनता दलने कर दिखाया। झारखण्ड मुक्ति मोर्चाके नेतागण भी अपने आदिवासी भाइयोंके बीच परिषदके गठनका श्रेय स्वयंको देते हैं। लेकिन पथरों और खदानोंके बीच कंक्र्रीटमें अपनी किस्मत फोड़ती आदिवासी जनता इन सारे झंझावातोंसे बेखबर है।

आदिवासियोंको न तो यह मालूम है कि चार राज्योंके २७ जिलोंको मिलाकर अलग झारखण्ड राज्यके गठनकी मांग करनेवाले आदिवासी नेताओंने झारखण्ड स्वशासी परिषदपर ही कैसे सन्तोष कर लिया न ही इस बातकी उन्हें जानकारी है कि भुखमरीकी शिकार जनताके प्रतिनिध इतना मालामाल कैसे हो गये। पिछले वर्ष आदिवासी जिला पलामूके भयंकर सूखाग्रस्त इलाकोंका दौरा करने जब प्रधान मन्त्री आये उस समयतक उस जिलेके कोई विधायक या सांसद उनका हालचाल लेने नहीं पहुंचे थे। मुख्य मन्त्री लालूप्रसाद प्रधान मन्त्रीके साथ गये।

पिछले वर्ष झारखण्ड इलाकोंमें लगातार कई-कई बार झारखण्ड पार्टियोंने हिंसात्मक तरीकेसे बन्द आयोजित किये जिससे सबसे ज्यादा केन्द्रको नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि खनिजका भण्डार झारखण्ड इलाकेमें है जिसका भरपूर लाभ केन्द्रको मिलता है। राज्य सरकारने कानून और व्यवस्था बनाये रखनेमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। आखिरकार प्रधान मन्त्रीको कहना पड़ा कि १५ अगस्ततक इस समस्याका वे हल निकाल लेंगे, लेकिन १५ अगस्त न सही, ३० सितम्बरतक उन्होंने हल निकाल दिया। समझौताका भाजपा, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (कृष्णामार्डी गुट), झारखण्ड पीपुल्स पार्टी और सी. पी. आई. (माले) ने यह कहकर विरोध किया था कि समझौता भोलीभाली आदिवासी जनताके साथ धोखा है। अब भाजपाको छोड़कर सभी पार्टियां चाहती हैं कि कुर्सीकी बन्दरबांटमें उन्हें भी हिस्सा मिले। कृष्णामार्डीके गुटवाला झारखण्ड मुक्ति मोर्चा वो तबका है जिसने श्री शिबू सोरेनसे अलग होकर श्री लालूप्रसादका साथ दिया था आज उसीका पता कट रहा है।

-शशिधर खा